



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आषाढ़ 1933 (श०)

(सं० पटना 298) पटना, सोमवार, 27 जून 2011

सं० प्र०२/ब्रेडा अपरा नीति-११/०८—२८४५  
ऊर्जा विभाग

संकल्प

24 जून 2011

विषय:- “बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति 2011”

जन मानस की ऊर्जा आवश्यकताएँ निरन्तर बढ़ती जा रही है, परन्तु पारम्परिक ऊर्जा स्रोत इस बढ़ती हुई मॉग की पूर्ति न कर सकने के साथ—साथ पर्यावरण पर भी दबाव डाल रहे हैं। अतः गैर पारम्परिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन एवं विकास पर बल देने की अत्यन्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के संवर्द्धन हेतु बिहार सरकार द्वारा ‘गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत’ वर्ष 2003’ में निरुपित किये गये थे, जो वर्ष 2008 तक प्रभावी था।

बिहार राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की प्रचुर संभावनाएँ हैं, जिनका अभी भी दोहन किया जाना शेष है, बिहार सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन के संवर्द्धन हेतु एक पुनरीक्षित नीति निर्धारण का निर्णय लिया है।

1. नाम एवं प्रवर्तन (लागू किया जाना)
  - 1.1 यह नीति ‘बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति 2011’ कही जायेगी।
  - 1.2 यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी। राज्य सरकार, आवश्यक समझे जाने पर, इसमें संशोधन कर सकेगी। इस प्रकार के संशोधन के अधीन यह नीति अधिसूचना जारी होने की अवधि से पॉच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी।
2. कार्य क्षेत्र एवं आच्छादन
  - 2.1 यह नीति बायोमास एवं बायोगैस आधारित परियोजना—सह—उत्पादन (को—जेनरेशन) परियोजनाओं, लघु/सूक्ष्म/छोटी पन—बिजली परियोजनाओं (25 मे.वा. तक), पवन ऊर्जा परियोजना, सौर परियोजनाओं, नगरीय ठोस अपशिष्ट आधारित परियोजनाओं एवं किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आधारित परियोजनाओं के साथ—साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के सभी प्रक्षेत्रों के संवर्द्धन हेतु लागू होगी।
  - 2.2 यह नीति सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लागू होगी।

- 2.3 यह नीति किसी भी उद्योग, संस्था, निजी अभिकरण, साझेदारी (पार्टनरशिप) फर्म, कम्पनी, संकाय, पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, सहकारी या पंजीकृत सोसाइटी (रजिस्टर्ड सोसाईटी), जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत संयंत्र लगाने एवं विद्युत उत्पादन करने के इच्छुक हों, के लिए लागू होगी ।
3. भूमि
- 3.1. औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी भूमि उपलब्ध होने एवं विकासक द्वारा पहचान किए जाने पर राज्य सरकार की भूमि उपलब्ध कराए जाने विषयक नीति के अनुसार पट्टे (लीज) पर दी जायेगी ।
- 3.2. परियोजना विकासक अपने स्तर पर निजी भूमि सीधे भू-स्वामियों से क्रय कर सकेंगे ।
- 3.3. कृषि योग्य भूमि को गैरकृषि कार्य के व्यवहार हेतु अनुमति दी जाएगी ।
4. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का कार्यान्वयन
- 4.1. परियोजना का अनुमोदन
- 4.1.1. परियोजना विकासक द्वारा आवेदन एवं स्थल विवरणी के अनुमोदन हेतु राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एस.आई.पी.बी.), उद्योग विभाग, बिहार सरकार को प्राक-सम्बाव्यता प्रतिवेदन और प्रयोज्य (लागू) प्रक्रिया फीस के साथ आवेदन देना आवश्यक होगा । ऐसी परियोजनाओं के आवेदन के मूल्यांकन एवं उसकी अनुशंसा के लिए, लघु/सूक्ष्म/छोटी पन-बिजली परियोजनाओं को छोड़कर जिसके लिए बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन (बी.एच.पी.सी.) नोडल एजेन्सी है, बिहार रिच्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी (ब्रेडा) नोडल एजेन्सी होगी ।
- 4.1.2. परियोजना विकासक को, जो राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से परियोजना पर स्थल/स्थान चयनित किए बिना प्रस्तावित परियोजना पर सहमति प्राप्त कर चुके हैं; उन्हें इस नीति के प्रभावी होने की तिथि से एक (1) माह की अवधि के भीतर स्थल चयन कर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की सहमति हेतु सम्यक रूप से सूचित करना होगा ।
- 4.2. प्रिड इन्टरफेसिंग एवम् इवैक्यूएशन की व्यवस्था
- 4.2.1. परियोजना विकासक अनिवार्यतः कैप्टिव परियोजना को छोड़कर अपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से उत्पादित विद्युत का न्यूनतम 25 प्रतिशत की आपूर्ति बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/[वितरण](#) लाइसेंसधारी को प्रस्तावित करेगा; तथापि ऐसी विद्युत की आपूर्ति के प्रस्ताव पर स्वीकृति पूरी तरह बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/[वितरण](#) लाइसेंसधारी के विवेक पर निर्भर होगा ।
- 4.2.2. ऐसी परियोजनाओं से प्रिड को अथवा प्रिड के माध्यम से तृतीय पक्ष को विद्युत की बिक्री के लिए परियोजना के विकासक को अपनी लागत पर प्रणाली का डिजाइन एवं निर्माण करना होगा; ताकि राज्य प्रिड/विद्युत बोर्ड प्रिड के साथ; विद्युत बोर्ड द्वारा निर्धारित विशिष्टियां एवं प्रचलित तथा समय-समय पर यथा संशोधित इंडियन इलेक्ट्रिसिटी प्रिड कोड/बिहार प्रिड कोड के अनुरूप इटरफेसिंग हो सके ।
- 4.2.3. परियोजना विकासक द्वारा निकटतम प्रिड/उपकेन्द्र तक उत्पादित विद्युत को ले जाने (इवैक्यूएशन) हेतु मीटरिंग एवं सुरक्षा उपकरणों सहित संचरण प्रणाली परियोजना की पूँजीगत लागत के व्यय का वहन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जायेगा, जो राशि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रदान कर दी जायेगी वशर्ते कि परियोजना विकासक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा उत्पादित बिजली में से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड या लाइसेंसधारी को कम से कम पचास प्रतिशत, न्यूनतम दो मेगावाट बिजली देने का प्रस्ताव देता है, अन्यथा बिजली को निकटतम प्रिड/उपकेन्द्र तक पहुँचाने की परियोजना का पूरा खर्च सारे मीटरों एवं सुरक्षात्मक उपकरणों की लागत सहित, परियोजना विकासक को वहन करना होगा ।
- 4.3. विद्युत का विक्रय/हवीलिंग
- 4.3.1. परियोजना विकासक अपने उपयोग के बाद शेष उत्पादित विद्युत को राज्य प्रिड/बिहार राज्य विद्युत बोर्ड प्रिड को बिक्री कर सकेगा, यदि शेष उत्पादित विद्युत 1 मेगावाट से अधिक उपलब्ध हो ।
- 4.3.2. परियोजना विकासक उत्पादित विद्युत की बिक्री तृतीय पक्ष को उत्पादित विद्युत का उपयोग उत्पादन स्थल पर अथवा अन्यत्र निजी उपयोग बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के नेटवर्क से लागू ओपेन एक्सेस प्रभार/अधिभार (सरचार्जेज) एवं अतिरिक्त अधिभार (सरचार्जेज) एवं बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित एवं समय-समय पर यथा संशोधित बिहार विद्युत विनियामक आयोग (ओपेन एक्सेस के निबंधन एवं शर्तों) विनियमावली 2006 अनुसार कोई अन्य प्रभार के भुगतान पर कर सकेगा, बशर्ते, तृतीय पक्ष कम से कम 1 मेगावाट लेने वाला हाईटेक्स्न उपभोक्ता हो । परियोजना विकासक ऐसी ऊर्जा के ओपेन एक्सेस एवं हवीलिंग के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ ओपेन एक्सेस एग्रीमेंट करेगा ।
- 4.3.3. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की बिक्री परियोजना विकासक एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बीच बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा यथा विहित विद्युत क्रय अनुबन्ध (पावर परचेज एग्रीमेंट-पी.पी.ए.) से, संचालित होगी ।
- 4.4. परियोजना का अनुश्रवण (मॉनिटरिंग)
- 4.4.1. इस नीति के प्रभाव में आने के बाद या राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के अनुमोदन की तिथि से, जो भी बाद में हो, सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित समय सारणी का पालन करेगी ।

कालावधि	गतिविधियों के मील के पत्थर
8 (आठ) महीने	आर्थिक संवृत्ति तथा परियोजना के लिए संयंत्र एवं कल-पुरजे के क्रय हेतु पक्का आदेश तथा अपेक्षित अग्रिम भुगतान अथवा आपूर्तिकर्ता संवेदकों के साथ अपरिवर्तनीय साख पत्रों का खोला जाना।
18 (अठारह) महीने	परियोजना के लिए संयंत्र एवं कल-पुरजे की कार्य स्थल पर अधिप्राप्ति
24 (चौबीस) महीने	चालू होना एवं वाणिज्यिक प्रचालन (उत्पादन)

कालावधि की गणना इस नीति के अधिसूचित होने की तिथि अथवा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा अनुमोदन की तिथि दोनों में से जो बाद में हो से की जायेगी।

4.4.2 राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा स्वीकृत सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को, ब्रेडा/बी.एच.पी.सी. को अद्वैत वार्षिक प्रतिवेदन देना होगा जिसके साथ विभिन्न विभागों/प्राधिकारों से प्राप्त यथा वांछित परमिट/स्वीकृति (विलयरेन्स)/सहमति की प्रतियां और उपर्युक्त 4.4.1 में वर्णित गतिविधियों के लक्ष्य प्राप्ति के दस्तावेजी साक्ष्य भी होंगे। अद्वैत वार्षिक प्रतिवेदन में संयंत्र की क्षमता, प्रक्रिया में परिवर्तन के व्योरे और स्पष्टीकरण अथवा कोई अन्य ऐसी सूचना, जो परियोजना के चालू होने की तिथि को प्रभावी करेगी, भी शामिल की जायगी।

4.4.3 राज्य निवेश पर्षद चालू किए जाने की समय-सूची को बढ़ा सकेगी और नयी समय सारणी दे सकेगी, बशर्ते कि:-

- (क) इसके पूर्व अन्य परियोजना विकासक को पुनरावलोकित परियोजना के लिए अनुमोदित/समनुदेशित नहीं किया गया हो।
- (ख) परियोजना विकासक कंडिका 4.4.1 के अधीन विहित अवधि की समाप्ति के 30 (तीस) दिन पूर्व परियोजना चालू होने में बिलम्ब के विश्वसनीय कारणों के उल्लेख के साथ राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को आवेदन करे।
- (ग) राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा परियोजना विकासक के आवेदन में उल्लिखित कारणों को विश्वसनीय समझा जाय।
- 5. प्रोत्साहन एवं इनकी प्रयोजनीयता
  - 5.1 सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन एवं इनकी प्रयोजनीयता निम्नांकित होगी।
    - 5.2 सभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं प्रभावी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, एवं राज्य सरकार की अन्य इस प्रकार के अन्य नीतियों के अधीन आच्छादित सुविधाओं का उपयोग करने की हकदार होंगी।
    - 5.3 व्यवहार्य स्थलों को चिह्नित एवं चयन किए जाने के संबंध में ब्रेडा/बी.एच.पी.सी. द्वारा आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जायेगी एवं सहयोग दिया जायेगा।
    - 5.4 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से उत्पादित बिजली विद्युत शुल्क से विमुक्त होगा।
    - 5.5 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु उपकरण एवं संयंत्र एवं मशीनरी इंट्री कर से विमुक्त होंगे।
    - 5.6 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के प्रस्ताव हेतु भारत सरकार एवं/अथवा बिहार सरकार, इंडियन रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एंजेंसी (इरेडा) एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम.एन.आर.ई.) के दिशा निर्देश एवं प्रोत्साहन अथवा योजना अनुसार ऋण प्रस्तावित (ऑफर) / उपलब्ध कराया जायेगा।
    - 5.7 लघु/सूक्ष्म/छोटी पनविजली योजनाओं से विद्युत उत्पादन की दशा में परियोजना विकासक द्वारा नहर के जल पतन (वाटर-फॉल) अथवा नदी के जल प्रवाह के उपयोग की अनुमति जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार की स्वीकृति एवं अनुबंध के पश्चात दी जायेगी। किन्तु, जल की विमुक्ति सिंचाई की मांग को देखते हुए की जायेगी।
    - 5.8 ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-14 का प्रावधान सभी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लागू होगा।
  - 6. विशेष छूट/बायोमास आधारित परियोजनाओं की प्रयोजनीयता
    - 6.1 परियोजनाओं के लिए बायोमास की उपलब्धता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद कुल समेकित क्षमता 2 मेगावाट से अधिक की बायोमास आधारित परियोजना के 25 किलो मीटर के दायरे में 2 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली किसी पूर्व स्वीकृति परियोजना की स्वीकृति नहीं देगी। किन्तु, राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के पास ऐसी परियोजना की क्षमता तथा किसी क्षेत्र में बायोमास की उपलब्धता को दृष्टिपथ में रख कर ऊर्पयुक्त क्षेत्र में वृद्धि अथवा कमी करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
    - 6.2 परियोजना विकासक परियोजना की क्षमता निर्धारित करने एवं राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को प्रस्ताव समर्पित करने के पूर्व संबंधित क्षेत्र में बायोमास उपलब्धता का आकलन करेगा।

- 6.3 इस नीति के प्रभावी होने के पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित लागू होंगे:
- 6.3.1 सभी संबंधित परियोजनाएं नोडल एजेन्सी ब्रेडा को परियोजना की प्रगति एवं अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करेंगा।
- 6.3.2 ऐसी परियोजनाओं कों, जिनके द्वारा कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की गयी है, का पुनरावलोकन नोडल एजेन्सी के द्वारा किया जायेगा और इसके बने रहने या निरस्तीकरण की अनुशंसा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को इस उद्देश्य से किया जाएगा कि उस क्षेत्र में अन्य गंभीर परियोजना विकासक को बायोमास आधारित परियोजना स्थापित करने की अनुमति दी जा सके।
- 6.3.3 स्वीकृत परियोजनाओं के बीच बायोमास क्षेत्र के संबंध में यदि कोई विवाद हो जिससे इन परियोजनाओं की निरन्तरता प्रभावित होती हो तो परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा की जायगी।
7. नवीकरणीय ऊर्जा क्रय आभार
- 7.1 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/वितरण लाइसेंसधारी, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के नवीकरणीय क्रय आभार (आर.पी.ओ.) के अन्तर्गत, सरकार की स्वीकृति के उपरान्त, बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा स्वीकृत टैरिफ के अनुरूप, निर्धारित न्यूनतम प्रमाणा (क्वान्टम) से अधिक, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत प्राप्त करने और आपूर्ति करने का प्रयत्न करेंगे। संचरण एवं वितरण प्रणाली में आवश्यक सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/वितरण लाइसेंसधारी को संबंधित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से क्रय किये गये विद्युत की सीमा तक करना होगा।
- 7.2 जहाँ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/वितरण लाइसेंसधारी बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निधारित दरों एवं शुल्क दरों पर उस नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन केन्द्र के विद्युत का क्रय करता हो वहाँ परियोजना विकासक संधारण/उत्पादन बंद रहने की अवधि में अपने लिए विद्युत उपभोग की अनुमति दी जाएगी, किन्तु, यदि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/वितरण लाइसेंसधारी उस विशिष्ट उत्पादन केन्द्र से विद्युत का क्रय नहीं करता हो तो बंद रहने/संधारण की अवधि में अपने उपभोग के लिए विद्युत प्राप्ति लागू यूआई। (यथा केन्द्रीय विनियामक आयोग द्वारा स्वीकृत) दरों पर अधिकतम यूआई। दर का 5 प्रतिशत जोड़ कर अथवा बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा ऐसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत क्रय हेतु स्वीकृत एवं लागू दर/शुल्क में से जो भी अधिक हो उस दर पर करेगा। आदेश—आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
शम्भु नाथ मिश्र,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

No. Pra 02/Breda Apra Niti-11/08—2845

Energy Deptt.

Resolution

*The 24<sup>th</sup> June 2011*

Subject:-“Bihar Policy for promotion of New and Renewable Energy Sources  
2011”

The energy need of the populace is increasing by the day, whereas the conventional source of energy is insufficient to meet the rising demand, Thereby adversely affecting the environment as well. Therefore there is an urgent need to develop and exploit non-conventional and renewable sources of energy in the state. With a view to promote the power generation from New and Renewable Energy sources, Government of Bihar formulated a policy as “Policy Guideline for Private Sector Participation for Developing Non-Conventional Energy Sources” in 2003, which ended in 2008.

Bihar has considerable potential for New and Renewable Energy sources, which is yet to be harnessed, the Government of Bihar resolved to issue a revised policy for promotion of power generation from various sources of New and Renewable Energy.

**1. Title and enforcement**

1.1 This Policy will be known as “Bihar Policy for promotion of New and Renewable Energy Sources 2011”

1.2 The policy will come into operation from the date of its notification. The government may modify this policy, if considered necessary. Subject to such modification, this policy will remain valid for a period of five years from its notification.

**2. Scope & Coverage**

2.1 The policy will be applicable for the development of all forms of New and Renewable Energy sources including biomass & Biogas based projects, cogeneration projects, mini/micro/small hydro projects (up to 25MW) wind power projects, Solar projects, municipal solid waste based projects and any other renewable resources based projects.

2.2 This policy will be applicable to all New and Renewable Energy projects. The policy shall be applicable for any industry, institution Private Agency, partnership firm, consortia, Panchayat Raj institutions, Urban Local bodies, co-operative or registered society desirous of installing and generating electricity from New and Renewable Energy Sources.

**3. Land**

3.1 Government land in the industrial area, if available and identified by the developer, may be leased in accordance with Government of Bihar policy for the allotment of land.

3.2 The project developer may purchase private land directly from the owners, on their own.

3.3 Use of agricultural land may be allowed for non-agricultural purposes.

**4. Implementation of New and Renewable Energy projects****4.1 Project approval:**

4.1.1 The project developer shall be required to submit the application to State Investment Promotion Board (SIPB), Department of Industries, Government of Bihar along with a pre-feasibility report, applicable processing fee & site details. The nodal agency for evaluation and recommendation of the application for such projects shall be Bihar Renewable Energy Development Agency (BREDA), except for mini/micro/small hydro projects for which Bihar State Hydro Electric Power Corporation (BSHPC) shall be the nodal agency.

4.1.2 The project developers, who have received the project approval from SIPB without specifying the site/location of the proposed projects, shall be required to identify the site/location and duly inform about the same to SIPB for approval within a period of one (1) month from the date of notification of this policy.

**4.2 Grid interfacing and evacuation arrangement**

4.2.1 The project developer shall necessarily offer to supply to Bihar State Electricity Board (BSEB)/Distribution Licensee a minimum of 25% of power generated from the respective New and Renewable Energy project, except for captive projects. However, the acceptance of such offer for supply of power shall be at the sole discretion of BSEB/Distribution Licensee.

- 4.2.2 The sale of power from such generation project to the grid or using the greed for wheeling of power the third parties will require the project developer to design and construct the system at its own cost, such that interfacing with the State grid/BSEB grid is done as per the latter's specifications & requirements/Indian Electricity Grid Code/ Bihar Grid Code as applicable and amended from time to time.
- 4.2.3 The capital cost of transmission system for evacuation of power to the nearest grid/ sub-station including all metering & protective instruments shall be born by BSEB, which shall be reimbursed to BSEB by the State Government, provided that the project developer offer to supply BSEB//Distribution Licensee at least 50%, subject to a minimum of 2 MW, of power generated from New and Renewable Energy projects. Else the entire project cost of transmission system for evacuation of power to the nearest grid/ sub-station including all metering & protective instruments shall be born by the project developer.
- 4.3 Sale/wheeling of Power**
- 4.3.1 Captive power project developer may sell the generated power to the State grid/BSEB after the captive consumption, if the power available is more than 1 MW.
- 4.3.2 The project developer may sell to third party/utilize generated power at the place of generation or at any other place for the captive use, through BSEB network on payment of applicable Open Access charges surcharges & additional surcharge and any other charges as approved/notified by Bihar Electricity Regulatory commission (BERC) and as per BERC (Terms & Conditions for Open Access) Regulation, 2006 as amended from time to time provided that the third party must be an HT consumer procuring at least 1MW power. The Project Developer shall execute an Open Access Agreement with the BSEB for availing open access and wheeling of such power.
- 4.3.3 The sale of electricity by the New and Renewable Energy project shall be governed by the Power Purchase Agreement (PPA) executed between Project Developer and BSEB, as prescribed by BERC.
- 4.4 Project Monitoring**
- 4.4.1 All New and Renewable Energy projects shall be required to adhere to the following schedule which is applicable from the date of notification of this policy or the date of SIPB approval whichever is later.

Activity milestones	Time period from zero date
Financial closure and placement of firm order for purchase of plant and machinery for the project and payment of requisite advance or opening of irrevocable letter of credit with suppliers/contractors	8 months
Receiving of plant and machinery for the project at site	18 months
Commissioning and commercial operation	24 months

\* Zero date shall be the date of notification of this policy or the date of SIPB approval, whichever a later.

**4.4.2** All New and Renewable Energy projects approved by SIPB, shall be required to submit to BREDA/ BSHPC, the half yearly reports incorporating the copies of the permits/ clearances/consents received from various departments/ authorities, as applicable and documentary evidence for the achievement of the activity milestones mentioned at Clause 4.4.1 above. The half yearly report shall also include details and explanations on the changes in plant capacity, process or any other relevant information which may affect the date of commissioning for project.

**4.4.3** Provided that SIPB may extend the time schedule for commissioning and provide the new schedule if .

- (a) No other project developer has been approved/ assigned for the reviewed project:-
- (b) The project developer makes an application to SIPB giving convincing reasons for delay in the completion of the project at least 30 days before the expiry of the prescribed period, as under para- 4.4.1
- (c) The reasons given by the project developer in the application are found convincing by SIPB.

#### 5. Incentives/applicability

The incentives and there applicability to all New and Renewable Energy projects are as under:-

5.1 All New and Renewable Energy projects will be entitled for benefits, available as notified from time to time, under the policies of the Central/State government.

5.2 All New and Renewable Energy projects shall be entitled to avail the facilities available under prevalent Industrial Incentive Policy, and such other policies of the Govt. of Bihar,

5.3 BREDA/BSHPC will provide necessary information and assistance regarding identification and selection of feasible sites.

5.4 The electricity generated from the New and Renewable Energy projects shall be exempted from electricity duty.

5.5 Entry tax on New and Renewable Energy sources devices and or equipment and or machinery shall be exempted.

5.6 Loans as per guidelines and incentives or schemes of the Government of India and or Government of Bihar, India Renewable Energy Development Agency (IREDA) and Ministry of New and Renewable Energy Govt. of India (MNRE) will be offered/ available for proposal of power generation through New and Renewable Energy Sources.

5.7 In case of power generation from mini/micro/small hydel schemes, project developer shall be allowed to use canal water- fall or river water flow subsequent to the approval and agreement with Water resources Department, Government of Bihar. However, the water will be released based on irrigation demand.

5.8 The provision of section 14 of Electricity Act 2003 for generation and distribution of electricity in rural areas will be applicable of all New and Renewable Energy projects.

#### 6. Special concessions/applicability for Biomass based projects.

6.1 In order to ensure availability of biomass and sustainability of such projects having aggregate capacity of more than 2MW - SIPB shall not approve any other biomass based project within a radial distance of 25Km from the approved project. However, SIPB reserves the right to reduce or increase the above area, while keeping in view the availability of biomass in that area.

6.2 The project developer shall carry out the biomass assessment in the region before finalizing the capacity of the project and submitting the proposal for approval to the SIPB.

6.3 The following shall be applicable for those projects which have been approved before the coming into operation of this policy.

6.3.1 All the projects have to submit a progress report and the current status of the project to the nodal agency concerned i.e. BREDA.

6.3.2 Such projects which have not made any significant progress shall be reviewed by the nodal agency and the recommendation for the continuance or cancellation shall be provided to SIPB with an objective of allowing other serious promoters in that area to set-up biomass based projects.

6.3.3 Among the approved projects, if there is a conflict of area of biomass which may effect the sustainability of these projects, based on the progress made in the projects, suitable measures will be taken by SIPB.

## 7. Renewable Energy Purchase Obligations

7.1 BSEB/Distribution Licensee shall endeavor to procure and supply the power from New and Renewable Energy Sources, more than the minimum quantum prescribed under the RPO obligations by BERL, with the approval of Government, in line with tariff approved by BERL. Due grid strengthening and up gradation in the transmission & distribution system shall be undertaken by BSEB/Distribution Licensee to the extent of power procured by BSEB/Distribution Licensee from respective New and Renewable Energy Project.

7.2 The project developer will be allowed to draw energy for their consumption during maintenance/ shut down period of the project, where BSEB/ Distribution Licensee is procuring power from that generating station , at the rate/tariff as approved by BERC for such New and Renewable Energy project, However, if BSEB/Distribution Licensee is not procuring power from that particular generation station, the drawl of energy for their consumption during shut down/maintenance period shall be at the applicable UI rate (as approved by CERC) plus 5% of maximum UI rate or the applicable rate/tariff as approved by BERC for purchase of power from such New and Renewable Energy project, whichever is higher.

Order:—Ordered to be published in the coming extra ordinary issue of Bihar Gazette for information to all.

By order of the Governor of Bihar,  
SHAMBHU NATH MISHRA,  
*Joint Secretary to Government.*

## अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 298-571+500-डी०टी०पी०।

**Website:** <http://egazette.bih.nic.in>